

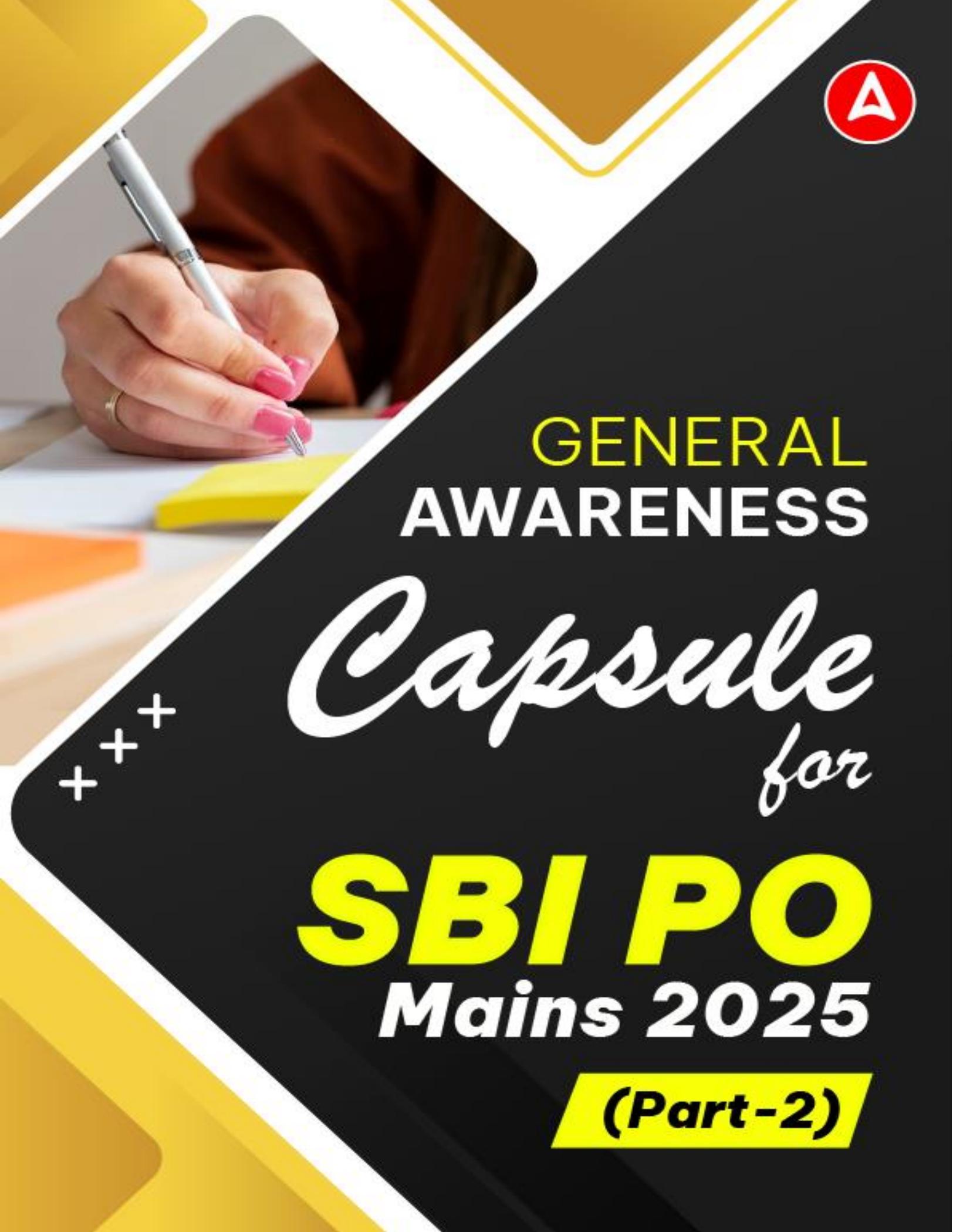


GENERAL
AWARENESS

Capsule
for

SBI PO
Mains 2025

(Part-2)





Contents

राष्ट्रीय समाचार.....	3
सरकारी योजनाएँ.....	13
अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स.....	14
बैंकिंग और फाइनेंस.....	14
अर्थव्यवस्था और व्यापार.....	15
समझौता ज्ञापन एवं समझौते.....	16
नियुक्तियाँ और इस्तीफे.....	16
पुरस्कार.....	17
शिखर सम्मेलन, कार्यक्रम और सम्मेलन.....	18
इंडेक्स.....	19
रक्षा.....	20
विज्ञान प्रौद्योगिकी.....	21
खेल.....	21
पुस्तक एवं लेखक.....	23
निधन.....	23
महत्वपूर्ण दिवस.....	24
विविध.....	25
स्थैतिक टेकअवे.....	25





राष्ट्रीय समाचार

माह की महत्वपूर्ण खबरें

संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

संसद ने 26 मार्च 2025 को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी मिली। इस संशोधन के तहत, बैंक खाता धारक अब चार नामांकित व्यक्ति (नोमिनी) जोड़ सकते हैं, जिससे वित्तीय योजना में अधिक लचीलापन आएगा। इसके अलावा, 'महत्वपूर्ण हित' (Substantial Interest) की परिभाषा को संशोधित कर इसकी सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई, जो लगभग छह दशकों के बाद हुआ बड़ा बदलाव है। विधेयक में सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल, वैधानिक लेखा परीक्षक (Auditor) के पारिश्रमिक, तथा नियामक अनुपालन रिपोर्टिंग तिथियों को भी संशोधित किया गया है।

मुख्य प्रावधान

1. चार नामांकित व्यक्ति (Nominee) जोड़ने की सुविधा

- अब बैंक खाता धारक चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं, जबकि पहले केवल एक ही नोमिनी की अनुमति थी।
- यह नियम कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों पर लागू होगा।
- लॉकर खातों के लिए सिर्फ संयुक्त नामांकन (Simultaneous Nomination) की अनुमति दी गई है।

2. 'महत्वपूर्ण हित' की नई परिभाषा

- बैंक में 'Substantial Interest' की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है।
- यह बदलाव 60 वर्षों के बाद किया गया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में बड़े निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

3. सहकारी बैंकों में सुधार

- निदेशकों का कार्यकाल (चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया।
- अब राज्य सहकारी बैंकों के बोर्ड में केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक भी शामिल हो सकते हैं।

4. बैंकिंग क्षेत्र में निगरानी और अनुपालन सुधार

- बैंकों को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक (Auditor Remuneration) तय करने में अधिक लचीलापन दिया गया।
- नियामक रिपोर्टिंग की तिथियां अब हर महीने की 15वीं और अंतिम तिथि होंगी, पहले यह दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती थी।

5. जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों (Wilful Defaulters) पर कड़ी कार्रवाई

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीए (Non-Performing Assets) को कम करने और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- पिछले 5 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 112 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की गई।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में ₹1.41 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में और अधिक लाभ वृद्धि की उम्मीद है।

7. व्यापक बैंकिंग सुधार

- यह संशोधन पांच अलग-अलग बैंकिंग कानूनों को प्रभावित करता है, जिससे यह बैंकिंग इतिहास में एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। यह विधेयक भारत के बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, लचीला और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तराखंड में सरकार ने बदले 15 स्थानों के नाम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। यह निर्णय जनभावनाओं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप लिया गया है। सरकार का उद्देश्य महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देना और राज्य के लोगों में प्रेरणा जगाना है।

संस्कृति और जनभावना से जुड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन स्थानों के नए नाम उन महापुरुषों के सम्मान में रखे गए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य सरकार के अनुसार, यह बदलाव जनसामान्य की मांग और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया गया है।

उत्तराखंड में बदले गए स्थानों की सूची

चार जिलों—हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में स्थानों के नाम बदले गए हैं।

हरिद्वार जिले में बदले गए नाम:

- औरंगजेबपुर → शिवाजी नगर
- गाजीवाली → आर्य नगर
- चांदपुर → ज्योतिबा फुले नगर
- मोहम्मदपुर जाट → मोहनपुर जाट
- खानपुर कुर्सली → अंबेडकर नगर
- इंद्रिथपुर → नंदपुर
- खानपुर → श्रीकृष्णपुर
- अकबरपुर फजलपुर → विजय नगर

BANK MAHAPACK
for all Bank & Insurance Exams
Selection Ka Saathi





देहरादून जिले में बदले गए नाम:

- मियांवाला → रामजी वाला
- पीरवाला → केशरी नगर
- चांदपुर खुर्द → पृथ्वीराज नगर
- अब्दुल्ला नगर → दक्ष नगर

नैनीताल जिले में बदले गए नाम:

- नवाबी रोड → अटल मार्ग
- पंचकड़ी से आईटीआई रोड → गुरु गोलवलकर मार्ग

ऊधम सिंह नगर जिले में बदला गया नाम:

- सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका → कौशल्या पुरी

नाम परिवर्तन के पीछे के प्रमुख कारण:

1. ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान - शिवाजी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम से स्थानों का नामकरण, उनके योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया।
2. सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना - मुगलकालीन और औपनिवेशिक युग के नामों को हटाकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नाम दिए गए।
3. जनभावनाओं का सम्मान - लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा किया।
4. राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव - इस कदम को संस्कृति संरक्षण का प्रयास माना जा रहा है, हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि केवल नाम बदलने से बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे हल नहीं होंगे।

नाम परिवर्तन का प्रभाव:

- संस्कृति का पुनरुत्थान - लोगों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
- शैक्षिक महत्व - नई पीढ़ी को ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
- राजनीतिक प्रभाव - सरकार को संस्कृति संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होगा।
- स्थानीय भावना का उत्थान - क्षेत्रीय गौरव और ऐतिहासिक चेतना को बल मिलेगा।

संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

भारतीय संसद ने हाल ही में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उनकी निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विधायी उपाय पारित किए हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर संसद के दोनों सदन में चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। राज्यसभा ने शुरुवार तड़के एक 12 घंटे लंबी मैराथन बहस के बाद इन विधेयकों को पारित किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के विरोध में पारित किया गया। इससे पहले, लोकसभा ने गुरुवार को इस विधेयक को 288-232 मतों के अनुपात में मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, राज्यसभा ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी पारित किया, जिसे 17 घंटे की लंबी बैठक के बाद सुबह 4 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले मंजूरी मिली।

प्रमुख बिंदु

विधेयक का उद्देश्य

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के संचालन को सुव्यवस्थित बनाना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह वक्फ संपत्तियों की निगरानी करने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और उनके कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।

लोकसभा/राज्यसभा में पारित

- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को नया नाम दिया गया है:
- "यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMED) विधेयक"।
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पारित हुआ, जिसने मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त कर दिया।

संसदीय प्रक्रिया

- विधेयक राज्यसभा में 128-95 मतों से पारित हुआ, 12 घंटे की बहस के बाद।
- लोकसभा में यह 288-232 मतों से पारित हुआ।
- बहस में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, उनके उपयोग, और विवाद समाधान में न्यायाधिकरणों की भूमिका पर चर्चा हुई।

मंत्रीगणों के वक्तव्य

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक का समर्थन किया और इसके प्रावधानों को सदन में प्रस्तुत किया।

पृष्ठभूमि

दो विधेयक प्रस्तुत किए गए:

1. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
2. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024

उद्देश्यों की रूपरेखा:

- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
 - वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन कर प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान।
 - वक्फ बोर्डों की कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार।
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
 - उपनिवेशकालीन 1923 के कानून को समाप्त करना।
 - एक समान, पारदर्शी और जवाबदेह वक्फ प्रबंधन सुनिश्चित करना।

'वक्फ' का अर्थ

- धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से इस्लामिक कानून के अंतर्गत समर्पित संपत्ति।
- बिक्री या अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग निषिद्ध।
- स्वामित्व अल्लाह को समर्पित माना जाता है; यह अविकारी (irrevocable) होता है।
- प्रबंधन मुतवल्ली करता है, जो वक़िफ (समर्पणकर्ता) की ओर से होता है।





‘वक्फ’ की उत्पत्ति

- दिल्ली सल्तनत काल में शुरू, जब सुल्तान मुइजुद्दीन साम गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को गांव समर्पित किए।
- इस्लामी सल्तनतों के साथ वक्फ संपत्तियाँ बढ़ीं।
- 1913 का कानून भारत में वक्फ को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था।

संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचा

- धार्मिक एवं परोपकारी संस्थाएँ संविधान की समवर्ती सूची में आती हैं।
- केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
- वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत शासित।

वक्फ कैसे बनता है

- मौखिक या लिखित घोषणा द्वारा।
- लंबे समय से धार्मिक/परोपकारी उपयोग में भूमि।
- वंश समाप्ति के बाद की गई संपत्ति की वसीयत।

सबसे अधिक वक्फ संपत्तियाँ वाले राज्य

- उत्तर प्रदेश – 27%
- पश्चिम बंगाल – 9%
- पंजाब – 9%

वक्फ कानूनों का विकास

- 1913 अधिनियम: वक्फ को वैध माना।
- 1923 अधिनियम: संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य।
- 1954 अधिनियम: केन्द्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना।
- 1995 अधिनियम: न्यायाधिकरणों का प्रावधान, विद्वानों और निर्वाचित सदस्यों की भागीदारी।

नए विधेयक में प्रमुख संशोधन

केन्द्रीय वक्फ परिषद का गठन

- अध्यक्ष: संबंधित मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री (पदेन)।
- सदस्य: सांसद, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुस्लिम कानून के विद्वान।
- दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

राज्य वक्फ बोर्ड का गठन

- राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग से एक व्यक्ति नामित कर सकती है।
- दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता।
- शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से प्रतिनिधित्व।
- दो मुस्लिम महिला सदस्यों की अनिवार्यता।

न्यायाधिकरण का गठन

- मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाया गया।
- अध्यक्ष: जिला न्यायाधीश स्तर का अधिकारी।
- सदस्य: संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी।

न्यायाधिकरण के आदेशों पर अपील

- पहले कोई अपील की व्यवस्था नहीं थी।
- अब: उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की अनुमति।

संपत्ति का सर्वेक्षण

- अब जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी सर्वेक्षण का नेतृत्व करेंगे।

सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा

- सरकारी संपत्ति वक्फ घोषित होने पर उसकी वक्फ स्थिति समाप्त होगी।
- राजस्व रिकॉर्ड कलेक्टर द्वारा अद्यतन किए जाएंगे।

ऑडिट

- ₹1 लाख से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य द्वारा नामित ऑडिटर से ऑडिट होगा।

केन्द्रीय पोर्टल

- स्वचालित वक्फ प्रबंधन के लिए डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था।
- पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु।

संपत्ति समर्पण की पात्रता

- कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं (पूर्व-2013 नियम बहाल)।

महिलाओं की विरासत सुरक्षा

- वक्फ बनाने से पहले महिलाओं को विरासत का अधिकार मिलना आवश्यक।
- विधवा, तलाकशुदा महिलाओं व अनाथों के लिए विशेष प्रावधान।

विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- वक्फ संपत्तियों की डिजिटल सूची से पारदर्शिता और विवादों में कमी आएगी।
- महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

चिंताएं

- गैर-मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में अनिवार्य, जिससे बहुसंख्यक सदस्य गैर-मुस्लिम होने की आशंका, जो हिंदू व सिख ट्रस्टों में नहीं होता।
- न्यायाधिकरण से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की हटाई गई भूमिका विवाद समाधान की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है।
- वक्फ निर्माण के लिए 5 वर्षों का मुसलमान होने की शर्त, इसका औचित्य स्पष्ट नहीं।

बिम्स्टेक: पूर्ण स्वरूप, सदस्य देश, उद्देश्य और क्षेत्रीय सहयोग का महत्व

छठा BIMSTEC शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल, 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के उद्देश्य से छह प्रमुख परिणामों को मंजूरी दी, साथ ही 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण भी अपनाया।

छठा BIMSTEC शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल, 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के उद्देश्य से छह प्रमुख परिणामों को मंजूरी दी, जिसमें 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साझा दृष्टिकोण शामिल था।

BIMSTEC क्या है?

BIMSTEC का फुल फॉर्म Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सुरक्षा, संपर्क और सतत विकास सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।





ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गठन की तिथि:

6 जून, 1997

वास्तविक नाम:

BIST-EC - बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग

वर्तमान नाम:

BIMSTEC - बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (जुलाई 2004 में बैंकॉक में प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान इसका नाम बदल दिया गया था।)

संस्थापक सदस्य देश (1997)

संगठन की स्थापना चार संस्थापक देशों के साथ की गई थी :

- बांग्लादेश
- भारत
- श्रीलंका
- थाईलैंड

इन देशों ने 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता:

- अबुल हसन चौधरी (बांग्लादेश)
- सलीम इकबाल शेरवानी (भारत)
- डीपी विक्रमसिंघे (श्रीलंका)
- पिटक इंद्राविट्टानुंत (थाईलैंड)

सदस्यता का विस्तार

म्यांमार

- 22 दिसंबर 1997 को शामिल हुए
- म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर BIMST-EC कर दिया गया

नेपाल और भूटान

- दोनों फरवरी 2004 में शामिल हुए.
- अंतिम नाम BIMSTEC जुलाई 2004 में प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था.

वर्तमान सदस्य देश

वर्तमान में बिम्स्टेक में सात देश सदस्य हैं :

1. बांग्लादेश
2. भूटान
3. भारत
4. म्यांमार
5. नेपाल
6. श्रीलंका
7. थाईलैंड

ये देश बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं और सामरिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

BIMSTEC के मुख्य उद्देश्य

BIMSTEC का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा अपने सदस्यों के बीच सहयोग के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाना है।

विस्तार से मुख्य उद्देश्य:

- आर्थिक विकास: व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग करके सदस्य देशों के बीच तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- सामाजिक प्रगति: समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करके क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में कार्य करना।
- तकनीकी सहयोग: नवाचार और डिजिटल उन्नति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- कनेक्टिविटी: क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना।
- ऊर्जा सहयोग: ऊर्जा अन्वेषण, व्यापार और नवीकरणीय संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन: प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में सहयोग बढ़ाना।
- सुरक्षा एवं आतंकवाद निरोध: आतंकवाद निरोध और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों पर संयुक्त रूप से कार्य करना।

BIMSTEC का महत्व

- रणनीतिक अवस्थिति: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है, जिससे बिम्स्टेक दो गतिशील क्षेत्रों के बीच एक सेतु बन जाता है।
- SAARC का विकल्प: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के समक्ष चुनौतियों के कारण, बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक सक्रिय मंच के रूप में उभरा है।
- विकास पर ध्यान: कई अन्य क्षेत्रीय समूहों के विपरीत, बिम्स्टेक कई क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सतत विकास पर जोर देता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान - मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।

5 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग का प्रतिबिंब है।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार विवरण

- मिश्रा विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था।
- इससे पहले यह सम्मान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को दिया जा चुका है।
- पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नौ प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल है।
- पदक के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर जैसे प्रतीक अंकित हैं, जो भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।





ऐतिहासिक महत्व

- पदक पर अंकित धर्म चक्र साझी बौद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है जिसने दोनों देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को आकार दिया है।
- चावल के ढेरों से युक्त पुन कलश या औपचारिक बर्तन समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है।
- नवरत्न (नौ बहुमूल्य रत्न) को कमल की पंखुडियों से घिरे एक ग्लोब के अंदर दर्शाया गया है।

मोदी की टिप्पणी

- मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का प्रतिबिंब है।
- उन्होंने कहा कि मित्रता विभूषण प्राप्त करना न केवल उनके लिए बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के लिए भी सम्मान की बात है।

मोदी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान

- मोदी को 15 से अधिक देशों द्वारा राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल हैं,
- सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज का आदेश
- फिलिस्तीन राज्य का आदेश
- संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद
- ऑर्डर ऑफ फिजी
- मिस्र का नील नदी का आदेश
- मार्च 2025 में, मॉरीशस ने देश की यात्रा के दौरान मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया।

समारोह विवरण

- यह समारोह कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ।
- राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया।

भारत-श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता है। यह पहल लगभग 40 वर्षों बाद आई है, जब भारतीय शांति सेना (IPKF) को श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान तैनात किया गया था। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलंबो यात्रा और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुर कुमारा दिसानायके के साथ हुई चर्चाओं के दौरान संपन्न हुआ। यह दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक दृष्टिकोण और सुरक्षा व विकास के मामलों में बढ़ती परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। यह समझौता रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में केंद्रित दस प्रमुख समझौतों के व्यापक ढांचे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी को और गहरा करना है। भारत-श्रीलंका रक्षा समझौता और अन्य समझौतों के प्रमुख बिंदु:

रक्षा सहयोग

- यह रक्षा सहयोग पर पहला फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन (MoU) है।
- इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च स्तरीय वार्तालाप शामिल हैं।
- यह इस विचार को सुदृढ़ करता है कि दोनों देशों की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका द्वारा भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया।
- राष्ट्रपति अनुर कुमारा दिसानायके ने आश्वासन दिया कि श्रीलंकाई भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा।

ऊर्जा और अवसंरचना

- संपूर पावर प्रोजेक्ट
- इस परियोजना की शिलान्यास समारोह वर्चुअली आयोजित की गई।
- यह परियोजना श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाएगी।
- मल्टी-प्रोडक्ट ऊर्जा पाइपलाइन परियोजना
- भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर।
- त्रिकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजना।
- ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौता
- भारत और श्रीलंका की बिजली ग्रिड को जोड़ने का प्रस्ताव।
- इससे बिजली व्यापार और विद्युत निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी।

डिजिटल परिवर्तन

- भारत और श्रीलंका के बीच डिजिटल गवर्नेंस समाधानों को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर।
- श्रीलंका के डिजिटल परिवर्तन को तेज करने का उद्देश्य।

नवीकरणीय ऊर्जा पहल

- सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट
- 5,000 धार्मिक स्थलों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना की जाएगी।
- भारत द्वारा 17 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से वित्तपोषित।
- 25 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न होगी।
- इसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य और औषधि

- MoU के तहत साझेदारी
- भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रीलंका के स्वास्थ्य और मास मीडिया मंत्रालय के बीच।
- उद्देश्य: स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग।
- अलग समझौता ज्ञापन
- इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और श्रीलंका की नेशनल मेडिसिन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच।
- औषधीय मानकों और प्रथाओं में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए।

क्षेत्रीय समर्थन और विकास

- भारत ने 2.4 अरब श्रीलंकाई रुपये की सहायता योजना की घोषणा की।
- श्रीलंका के पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर केंद्रित।





प्रधानमंत्री मोदी ने नए पंवन ब्रिज का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में नए पंवन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह देश का पहला वर्टिकल-लिफ्ट समुद्री पुल है, जो सौ साल पुराने पंवन ब्रिज का स्थान लेता है और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को मांडपम (मुख्य भूमि) से जोड़ता है और इसे टिकाऊपन व तकनीकी उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन राम नवमी के पावन दिन और श्रीलंका से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के साथ हुआ, जहां उन्होंने राम सेतु का हवाई दर्शन भी किया। यह दिन आध्यात्मिक और संरचनात्मक दोनों दृष्टियों से भारत के लिए विशेष बन गया।

नए पंवन ब्रिज की प्रमुख विशेषताएं :

नया पंवन ब्रिज

- उद्घाटन तिथि: 6 अप्रैल 2025 (राम नवमी)
- उद्घाटनकर्ता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- स्थान: रामनाथपुरम ज़िला, तमिलनाडु
- उद्देश्य: रामेश्वरम द्वीप को मांडपम (मुख्य भूमि) से जोड़ना

ब्रिज की तकनीकी विशेषताएं

- कुल लंबाई: 2.07 किमी
- निर्माण लागत: ₹700 करोड़ से अधिक
- कार्यकारी एजेंसी: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), एक नवरत्न PSU
- डिजाइन प्रकार: वर्टिकल-लिफ्ट ब्रिज
- लिफ्ट स्पैन: 72.5 मीटर (17 मीटर तक ऊंचा किया जा सकता है, ताकि जहाज़ निकल सकें)
- ट्रैक क्षमता: दो रेलवे ट्रैकों के लिए डिजाइन, फिलहाल एक चालू
- ट्रेन गति क्षमता: 80 किमी/घंटा तक
- आयु: 100 वर्षों तक टिकाऊ

उन्नत निर्माण तकनीक

- स्टेनलेस स्टील रिइंफोर्समेंट
- पूरी तरह वेल्डेड जोड़
- समुद्री जंग से सुरक्षा के लिए हाई-ग्रेड पेंट व पॉलिसिलॉक्सेन कोटिंग
- न्यूनतम रख-रखाव वाला डिजाइन

Test Prime
ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION.

Logos for IAS, UPSC, SSC, Banking, and other exams.

वैश्विक तुलना व महत्व

- गोल्डन गेट ब्रिज (USA),
- टॉवर ब्रिज (UK),
- ओरेसुंड ब्रिज (डेनमार्क-स्वीडन) जैसी प्रतिष्ठित संरचनाओं से तुलना
- आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

प्रधानमंत्री मोदी के अन्य कार्यक्रम

- एक नए तटरक्षक जहाज़ को रवाना किया (जो ब्रिज के नीचे से गुज़रा)
- रामेश्वरम-तांबरम (चेन्नई) ट्रेन को हरी झंडी
- ₹8,300 करोड़ के रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला
- रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना

आध्यात्मिक पहलू: राम सेतु दर्शन

- श्रीलंका से लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी ने राम सेतु (एडम्स ब्रिज) का हवाई दर्शन किया
- यह दृश्य उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया
- यह घटना अयोध्या के सूर्य तिलक समारोह के साथ हुई — “दैवीय संयोग” बताया गया
- राम सेतु को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रमुखता दी गई

राम सेतु (एडम्स ब्रिज) के बारे में

- स्थान: रामेश्वरम (भारत) से मन्नार द्वीप (श्रीलंका) तक का समुद्री प्राकृतिक श्रृंखला
 - लंबाई: लगभग 48 किमी
 - उत्तर में: पाल्क जलडमरूमध्य (बंगाल की खाड़ी से जुड़ाव)
 - दक्षिण में: मन्नार की खाड़ी (हिंद महासागर से जुड़ाव)
- यह पुल न केवल भारत की इंजीनियरिंग उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति 2025: RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की घोषणा की है। 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% करने का निर्णय लिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी (SDF) दर को 5.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) व बैंक दर को 6.25% कर दिया गया है।

बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की, और इसमें डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगता भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव शामिल हुए। वर्ष 2025 के लिए अगली MPC बैठकें जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में निर्धारित हैं।

वर्तमान नीतिगत दरें:

नीति	दर
रेपो दर	6.00%
SDF दर	5.75%
MSF दर	6.25%
बैंक दर	6.25%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर	3.35%





RBI द्वारा घोषित 6 अतिरिक्त उपाय:

1. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) की सेक्युरिटाइजेशन की सुविधा प्रस्तावित।
2. सह-उधारी (co-lending) दिशानिर्देश सभी नियामक संस्थाओं व सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होंगे।
3. सोने के विरुद्ध ऋण (loan against gold) के लिए नए नियामक प्रावधान।
4. आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट (Partial Credit Enhancement) पर व्यापक दिशा-निर्देश।
5. NPCI को बैंकों और हितधारकों की सलाह से UPI के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन की सीमा ₹2 लाख से अधिक बढ़ाने की स्वतंत्रता।
6. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को विषय-तटस्थ (theme-neutral) और ऑन-टैप रूप में लागू किया जाएगा।

GDP वृद्धि अनुमान (RBI द्वारा):

अवधि	पूर्व अनुमान	नया अनुमान
FY26	6.7%	6.5%
Q1 FY26	6.7%	6.5%
Q2 FY26	7.0%	6.7%
Q3 FY26	6.5%	6.6%
Q4 FY26	6.5%	6.3%

CPI मुद्रास्फीति अनुमान (RBI द्वारा):

अवधि	पूर्व अनुमान	नया अनुमान
FY26	4.2%	4.0%
Q1 FY26	4.5%	3.6%
Q2 FY26	4.0%	3.9%
Q3 FY26	3.8%	3.8%
Q4 FY26	4.2%	4.4%

यह मौद्रिक नीति समीक्षा RBI के विकास व स्थिरता के संतुलन की ओर बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां व्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जबकि मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा गया है।

भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए सहमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। उनकी बातचीत रक्षा, तटरक्षक बल संचालन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और जनसंपर्क संबंधों में सहयोग को सशक्त बनाने पर केंद्रित रही। भारत में क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह यात्रा दोनों देशों की साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं और पारस्परिक आर्थिक हितों को रेखांकित करती है।

प्रमुख बिंदु

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- भारत और यूएई ने रक्षा एवं तटरक्षक बल सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई।
- तटरक्षक बल सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- शेख हमदान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई बातचीत में व्यापारिक संबंधों की तरह रक्षा संबंधों को भी ऊंचे स्तर तक ले जाने पर बल दिया गया।

प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान:

- संयुक्त प्रशिक्षण और आदान-प्रदान कार्यक्रम
- सह-उत्पादन और सह-विकास परियोजनाएं
- रक्षा निर्माण में सहयोग
- दोनों पक्षों ने इंडिया-यूएई डिफेंस पार्टनरशिप फोरम का स्वागत किया।
- मेक-इन-इंडिया और मेक-इन-एमिरेट्स पहलों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

उच्च स्तरीय राजनयिक संवाद

- प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हमदान की यात्रा को "गहरी मित्रता की पुष्टि" बताया।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी शेख हमदान से मुलाकात की और मजबूत संबंधों के लिए आभार जताया।
- शेख हमदान ने भारत-यूएई संबंधों को "विश्वास पर आधारित, इतिहास द्वारा आकारित" बताया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

- दुबई चैंबर ने मुंबई में दुबई-इंडिया बिज़नेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें 200 भारतीय व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया।
- महत्वपूर्ण व्यापारिक आँकड़े:
- भारत-यूएई गैर-तेल व्यापार (2023): \$54.2 बिलियन
- दुबई-भारत द्विपक्षीय व्यापार: \$45.4 बिलियन
- भारत में दुबई का निवेश: \$4.68 बिलियन

2024 में:

- 16,623 भारतीय कंपनियाँ दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स में शामिल हुईं।
- अब दुबई में 70,000 से अधिक भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं।

संपर्क और जन-सामान्य संबंध

- 2024 में दुबई ने 3.14 मिलियन दक्षिण एशियाई पर्यटकों का स्वागत किया, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारत से थी।
- नेताओं ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संपर्क के माध्यमों की भूमिका को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया।

कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए "जीवंत गांव कार्यक्रम-II (वीवीपी-II)" को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम - II' (VVP-II) को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित) के रूप में मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण के तहत 'सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (ILBs) से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के समग्र विकास में सहायक होगा, विशेषकर उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो VVP-I के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।

इस योजना की कुल लागत ₹6,839 करोड़ है और इसे वित्त वर्ष 2028-29 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश), लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में लागू किया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

- सीमावर्ती गांवों में बेहतर जीवन स्थितियों और पर्याप्त आजीविका के अवसरों का निर्माण
- सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सीमापार अपराधों पर नियंत्रण
- सीमावर्ती जनसंख्या को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सीमा सुरक्षा बलों की 'आंख और कान' के रूप में विकसित करना

कार्यक्रम के तहत मिलने वाली सुविधाएं:

- गांव या गांवों के समूह में बुनियादी ढांचे का विकास
- मूल्य श्रृंखला विकास (सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से)
- सीमावर्ती विशेष जागरूकता कार्यक्रम
- शिक्षा में सुधार हेतु स्मार्ट कक्षाएं
- पर्यटन सर्किट का विकास
- विविध और टिकाऊ आजीविका के अवसर

कार्यक्रम की सभी योजनाएं सीमाओं की जरूरतों और राज्यों तथा गांवों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होंगी, जिन्हें सहभागी दृष्टिकोण के तहत तैयार किए गए 'विलेज एक्शन प्लान' के अनुसार लागू किया जाएगा।

इन गांवों के लिए सभी मौसमों में सड़क संपर्क योजना पहले से ही मंजूर किए गए पीएमजीएसवाई-IV (MoRD) के अंतर्गत किया जाएगा। एक उच्चस्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, इन क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों में आवश्यक छूट पर विचार करेंगी।

कार्यक्रम की चार प्रमुख विषयगत प्राथमिकताएं:

1. सभी मौसमों में सड़क संपर्क
2. टेलीकॉम कनेक्टिविटी
3. टेलीविजन कनेक्टिविटी
4. विद्युतीकरण (वर्तमान योजनाओं के समन्वय के माध्यम से)

सामाजिक-सांस्कृतिक पहल:

इन गांवों में मेले, त्योहार, जागरूकता शिविर, राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के दौरे और रात्रि प्रवास जैसे कार्यक्रमों के आयोजन से गांवों की जीवंतता को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यटन की संभावना और स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और पीएम गति शक्ति जैसे सूचना डेटाबेस का सहारा लिया जाएगा। VVP-II, VVP-I के साथ मिलकर सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर और जीवंत बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है।

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारतीय रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत लगभग ₹18,658 करोड़ है। ये चार परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करती हैं और इससे भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

स्वीकृत परियोजनाएं:

1. संबलपुर - जरपड़ा तीसरी और चौथी लाइन
2. झारसुगुड़ा - ससों तीसरी और चौथी लाइन
3. खरसिया - नया रायपुर - परमलकसा पांचवीं और छठवीं लाइन
4. गोंदिया - बल्हारशाह दोहरीकरण परियोजना

इन परियोजनाओं से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता, दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों पर परिचालन को आसान बनाएंगे और भीड़भाड़ को कम करेंगे, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास संभव हो पाएगा।

ये सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "नए भारत" की परिकल्पना के अनुरूप हैं, जो इन क्षेत्रों में समग्र विकास कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेंगी।

विशेष बिंदु:

- ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जो बहु-मोडल कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं।
- परियोजनाओं के तहत 19 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।
- 2 आकांक्षी जिलों (गडचिरोली और राजनांदगांव) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
- लगभग 3350 गांवों और 47.25 लाख आबादी को इन परियोजनाओं से लाभ मिलेगा।
- खरसिया - नया रायपुर - परमलकसा रूट से बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे वहां नए औद्योगिक इकाइयों (जैसे सीमेंट प्लांट्स) की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी।

परिवहन और पर्यावरण पर प्रभाव:

- यह मार्ग कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसे महत्वपूर्ण माल की ढुलाई के लिए आवश्यक हैं।
- इन परियोजनाओं के माध्यम से 88.77 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा।
- रेलवे, एक पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के नाते, देश की जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, तेल आयात में 95 करोड़ लीटर की बचत, और CO₂ उत्सर्जन में 477 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी — जो कि 19 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

यह पहल न केवल रेलवे के बुनियादी ढांचे को सशक्त करेगी बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार, और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी।





अप्रैल महीने की राज्यवार महत्वपूर्ण घटनाएँ

असम

- रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल 2025 के मध्य में पूरे असम में मनाया जाएगा, जो असमिया नव वर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह जीवंत त्यौहार न केवल वसंत और फसल का उत्सव है, बल्कि असमिया पहचान, संस्कृति और सामुदायिक भावना की पुष्टि भी है।

हरियाणा

- केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, एक नए आईसीयू सुविधा का उद्घाटन किया और एक पीजी हॉस्टल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में अमित शाह ने हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत, इसकी सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य महत्ता को रेखांकित किया।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में अग्निवीरों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जो अग्निपथ योजना का हिस्सा हैं। राज्य अब पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण प्रदान करेगा, जिससे यह ऐसी गारंटी देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को उनकी सेवा के बाद सुरक्षित करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। सरकार ने स्वरोजगार के लिए किरायायती ऋण और निजी सुरक्षा भूमिकाओं में रुचि रखने वालों के लिए बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने में प्राथमिकता जैसे अन्य प्रावधान भी पेश किए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा घोषित उपायों और अग्निवीरों के लिए उनके निहितार्थों का विस्तृत अवलोकन प्रदान करना है।
- हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित दो हड़प्पा सभ्यता स्थलों - मिताथल और तिघराना - को आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। 4,400 साल से भी पुराने ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान हैं, जो हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के काल में प्रारंभिक कृषि समाजों, नगर नियोजन, शिल्प उद्योगों और व्यापार के विकास पर प्रकाश डालते हैं। हरियाणा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 के तहत हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अब इन स्थलों को कानूनी संरक्षण में लाया गया है। इस कदम का उद्देश्य इन प्राचीन बस्तियों को अतिक्रमण और क्षति से बचाना है, साथ ही बाड़ लगाने और सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।

महाराष्ट्र

- महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने 5 अप्रैल, 2024 को मुंबई के राजभवन में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेन्ट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने विकसित भारत में भारत के समुद्री क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया। राज्यपाल ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और शिपिंग महानिदेशालय, एससीआई, भारतीय रेलवे और निर्यातकों जैसे प्रमुख संगठनों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

पंजाब

- पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। नंगल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभिक बजट ₹10 करोड़ निर्धारित किया गया है। वहीं, श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये योजनाएँ 'बदलदा पंजाब' बजट 2025-26 का हिस्सा हैं, जिसे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्तुत किया।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु ने 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% दर्ज की, जो पिछले 10 वर्षों में राज्य की सर्वश्रेष्ठ वृद्धि है, जो मजबूत और स्थिर आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। वास्तविक विकास में मुद्रास्फीति शामिल नहीं है, जबकि नाममात्र विकास दर 14.02% रही, जो भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी 15.71 लाख करोड़ रुपये (2023-24) से बढ़कर 17.23 लाख करोड़ रुपये (2024-25) हो गई। कोविड-19 (2020-21 में 0.07% वृद्धि) जैसी चुनौतियों के बावजूद, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था ने लचीलापन और तेजी से सुधार दिखाया है।

उत्तराखंड

- नैनीताल के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत, नैनी झील, जल स्तर में गंभीर गिरावट का सामना कर रही है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम 4.7 फीट पर पहुंच गई है, जिससे संभावित पेयजल की कमी की चिंता बढ़ गई है। झील शहर की 76% पानी की मांग को पूरा करती है, लेकिन कम बारिश, कम बर्फबारी, अनियोजित विकास और प्रदूषण जैसे कारकों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। विशेषज्ञ चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राकृतिक कायाकल्प और सतत विकास प्रथाओं सहित समग्र संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 (जल संरक्षण अभियान) के तहत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को नौलों, धाराओं और वर्षा आधारित नदियों जैसे खतरे में पड़े जल स्रोतों की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, जिससे उनके संरक्षण के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलती है। अभियान की थीम, "धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा" जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई पर जोर देती है।

केंद्र शासित प्रदेश

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए एक निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य लैंगिक-समावेशी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई इस सेवा के तहत महिलाएं पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट सिटी ई-बसों और जेकेआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। इस पहल में शहरी क्षेत्रों में 200 ई-बसें और कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में 235 जेकेआरटीसी बसें शामिल हैं।





शुभारंभ और उद्घाटन:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया, जिससे वे नई रुचियाँ विकसित कर सकें और अपने कौशल को निखार सकें। अपने मासिक 'मन की बात' संबोधन में, उन्होंने अपने बचपन की गर्मी की छुट्टियों को याद किया और आज उपलब्ध विभिन्न शिक्षण अवसरों पर प्रकाश डाला, जिनमें प्रौद्योगिकी शिविर, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम और नेतृत्व प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण, वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन और योग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहरी विकास, सहकारी क्षेत्र, कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की गई।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में "नीति एनसीईआर राज्य आर्थिक मंच" पोर्टल लॉन्च किया, जिसे नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) के सहयोग से विकसित किया है। यह पोर्टल 1990-91 से 2022-23 तक भारतीय राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों पर डेटा के व्यापक भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य ऋण प्रबंधन, राजस्व सृजन सहित राज्य वित्त के प्रबंधन के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण प्रदान करना है।

Important Festival

- छोटानागपुर क्षेत्र, खास तौर पर झारखंड में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल उत्सव, वसंत ऋतु के आगमन और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। 1 अप्रैल, 2025 को आयोजित होने वाला यह उत्सव साल के पेड़ का सम्मान करता है, जिसे गांव की देवी सरना मां का निवास माना जाता है। यह त्यौहार सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से आदिवासी पहचान और अधिकारों को मुखर करने के लिए गहरा सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और राजनीतिक महत्व रखता है।
- पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल के 11वें संस्करण की शुरुआत पुडुचेरी के तमिल क्वार्टर में जीवंत 'वीधी विलायट्टू' (स्ट्रीट गेम्स) के साथ हुई, जिसमें 250 से ज्यादा बच्चे और कई निवासी शामिल हुए। ईश्वरन कोइल और अन्ना सलाई के बीच आयोजित इस फेस्टिवल में शहर की संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाया गया, जिसमें पल्लंगुड्डी, पम्बरम, धयम और पाच्चा कुथिराई जैसे पारंपरिक खेल शामिल थे। पीपल फॉर पांडिचेरी हेरिटेज और पाँडीकैन द्वारा सह-आयोजित इस कार्यक्रम ने समुदाय को सफलतापूर्वक जोड़ा, जिसमें पारंपरिक गतिविधियों, भोजन और मौज-मस्ती के साथ सड़कें जीवंत हो उठीं।

- माधवपुर मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने 6 अप्रैल, 2025 को रामनवमी के दौरान भगवान कृष्ण और रुक्मणीजी के दिव्य मिलन के उपलक्ष्य में किया था। पोरबंदर के माधवपुर में आयोजित यह सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एकता और सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक है। 2018 में इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा दिए जाने के बाद से, इस मेले का महत्व बढ़ गया है और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया जैसे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पटेल ने धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करते हुए रुक्मणी मंदिर में नई तीर्थ सुविधाओं का भी शुभारंभ किया।

Miscellaneous National News

- 4 अप्रैल, 2025 को भारतीय रेलवे ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य ट्रेन के पहियों की जल्दी और सुरक्षित जांच के लिए ऑटोमैटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम नामक स्मार्ट मशीनें लगाना है। यह आधुनिक और बेहतर रेलवे रखरखाव की दिशा में एक कदम है।
- व्यापक वित्तीय समावेशन को समर्थन देने के लिए, इंडिया पोस्ट ने निष्पांन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है, ताकि घर-घर जाकर केवाईसी सत्यापन सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिससे सभी के लिए, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए निवेश प्रक्रिया सरल हो सके।
- ब्रासीलिया में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच एकजुट जलवायु नेतृत्व की जोरदार वकालत की। सतत विकास और 2030 जलवायु एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने की रणनीति के रूप में "बाकू से बेलेम रोडमैप" का प्रस्ताव रखा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल, 2025 को छोटे बिस्मटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा जुबर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को जोड़ना था। यह स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास था।
- केंद्र सरकार ने देश भर में 440 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित करने की एक बड़ी पहल की है। इन विद्यालयों का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, खासकर उन ब्लॉकों में जहाँ 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी है।
- राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 12 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। यह मंजूरी लोकसभा द्वारा 288-232 मतों से विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद मिली।





- नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे ने फरवरी 2025 तक 2,249 स्टेशनों और सेवा भवनों में 209 मेगावाट सौर ऊर्जा सफलतापूर्वक स्थापित की है। यह एक असाधारण वृद्धि दर को दर्शाता है, पिछले 5 वर्षों में 1,489 नए सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं।
- 27 मार्च, 2025 तक केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र के हिस्से से कोई धनराशि नहीं मिली है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन स्वीकृत हो चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में CPI(M) MP जॉन त्रिटास द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह खुलासा किया।
- भारत सरकार ने बिहार में दो परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे की पहलों को हरी झंडी दे दी है - पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना। इन परियोजनाओं को पीएम के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मंजूरी दे दी है।
- नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को "नीति एनसीआईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम" पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, एक नए आईसीयू सुविधा का उद्घाटन किया और एक पीजी हॉस्टल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में अमित शाह ने हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत, इसकी सांस्कृतिक,

आर्थिक और सैन्य महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने महाराजा अग्रसेन के आर्थिक सहयोग और सामाजिक कल्याण पर आधारित शासन मॉडल की प्रशंसा की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों से जोड़ा।

- नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey - PLFS) के अनुसार, जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है — जो 2023 में 5.0% थी, वह 2024 में घटकर 4.9% हो गई है। यह रिपोर्ट यह संकेत देती है कि रोजगार के अवसरों में मामूली सुधार हुआ है, हालांकि क्षेत्रवार (सेक्टर वाइज) और लिंग आधारित (जेंडर वाइज) असमानताएँ अब भी बनी हुई हैं।
- वैश्विक विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, आईआईएम-अहमदाबाद यूएई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलने के लिए तैयार है। यह परिसर सितंबर 2025 में दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी (DIAC) में शुरू होगा, जो वैश्विक पेशेवरों और उद्यमियों के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रम प्रदान करेगा।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने एम्स नई दिल्ली द्वारा विकसित इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चेहरे की पहचान और स्वचालित वर्कफ्लो का उपयोग करके रोगी रेफरल को सुव्यवस्थित करना और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। शुरुआत में एम्स नई दिल्ली और एम्स बिलासपुर के बीच शुरू किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य एम्स अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी रोलआउट करना है। इसके मुख्य लाभों में प्रतीक्षा समय में कमी, बड़ी हुई सुरक्षा और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण शामिल हैं, साथ ही किफायती आवास के लिए विश्राम सदन पोर्टल में एकीकरण भी शामिल है - जो भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

सरकारी योजनाएँ

केंद्रीय सरकार की योजनाएँ

पहल का नाम	उद्देश्य
स्माइल (SMILE) कार्यक्रम	भारत के लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना, लागत में कमी लाना और कार्यक्षमता बढ़ाना। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गति शक्ति का समर्थन करता है और बहु-मोडल परिवहन, वेयरहाउसिंग का मानकीकरण और डिजिटल व्यापार लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देता है।
"एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)" नीति	43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 28 में एकीकरण करके परिचालन दक्षता में सुधार और प्रतिस्पर्धा में कमी लाना। यह नीति ऋण प्रवाह को बेहतर बनाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण को सशक्त करती है, साथ ही लागत और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करती है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)	5 अप्रैल 2025 को दिल्ली 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बना जिसने यह योजना लागू की। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना, जिसमें 50 करोड़ लाभार्थी और 36 लाख फ्रंटलाइन कार्यकर्ता शामिल हैं। दिल्ली में 10 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होंगे।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	8 अप्रैल 2025 को इस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। 2015 में शुरू हुई यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना जमानत ऋण देकर उन्हें वित्तीय सहायता देती है। अब तक ₹32.61 लाख करोड़ के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यह नौकरी खोजने वालों को नौकरी देने वाले उद्यमी में बदलने का प्रयास है।





पहल का नाम	उद्देश्य
सागरमाला कार्यक्रम	मार्च 2015 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम भारत के समुद्री क्षेत्र को आधुनिक बनाने और बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी में सुधार, औद्योगिक विकास और तटीय शिपिंग व अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देकर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को सशक्त किया जाता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मजदूरी दरों में 2.33% से 7.48% की वृद्धि। कुछ राज्यों में मजदूरी ₹400 प्रतिदिन तक पहुंची (हरियाणा में सर्वाधिक)। यह पहली बार है जब किसी राज्य में NREGS के तहत इतनी अधिक मजदूरी तय की गई है।

राज्य सरकार की योजनाएँ

पहल का नाम	उद्देश्य और विवरण
स्वर्ण आंध्र - 2047 विजन (Swarna Andhra-2047)	"Zero Poverty - P4 नीति" की शुरुआत उगादी (30 मार्च 2025) को। 'P4' (Public-Private-People Partnership) मॉडल पर आधारित यह पहल 2047 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखती है। इसमें आवास, शौचालय, जल, एलपीजी, सौर ऊर्जा, इंटरनेट और उद्यमिता पर ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (असम)	असम सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया सबसे बड़ा महिला उद्यमिता कार्यक्रम। 30 लाख महिलाओं को माइक्रो-बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए ₹10,000 बीज पूंजी। सफल उद्यमियों को दूसरे वर्ष ₹25,000 और तीसरे वर्ष ₹50,000 की वित्तीय सहायता।
स्टैंड-अप इंडिया योजना	5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) और महिलाओं को उद्यम शुरू करने हेतु ऋण सहायता देती है। अब तक ₹61,000 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत। महिलाओं के ऋण खाते 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हुए। यह वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन में सहायक रही है।

अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स

- 4 अप्रैल, 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले दो वर्षों के लिए BIMSTEC का नया अध्यक्ष बन गया। इसे पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व प्राप्त हुआ। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश BIMSTEC को अधिक समावेशी (सभी को शामिल करना) और कार्रवाई-उन्मुख (वास्तविक परिणामों पर केंद्रित) बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसा कि UNCTAD के वैश्विक 'अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए तत्परता' सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंचने से पता चलता है। यह 2022 में 48वें स्थान से एक बड़ी छलांग है, जो अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रगति से प्रेरित है।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित "रेसीप्रोकल टैरिफ" नीति एक बार फिर सुर्खियों में है। इस प्रस्तावित टैरिफ ढांचे के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 27% समायोजित पारस्परिक टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे अमेरिकी मार्क में भारतीय वस्तुओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित "रेसीप्रोकल टैरिफ" नीति एक बार फिर सुर्खियों में है।
- सऊदी अरब ने हज यात्रा के दौरान भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के लोगों पर अस्थायी वीजा प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उमराह वीजा, व्यावसायिक यात्रा वीजा और पारिवारिक यात्रा वीजा को प्रभावित करता है और इसका उद्देश्य आगंतुकों के प्रवाह को नियंत्रित करना, अवैध रूप से अधिक समय तक रुकने से रोकना और एक सुचारू और सुरक्षित हज सीजन सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबंध जून 2025 के मध्य में हज यात्रा के अंत तक लागू रहेगा।
- कजाकिस्तान ने करागांडा क्षेत्र में कुइरेक्तीकोल साइट पर दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का अब तक का सबसे बड़ा भंडार खोजा है, जिसका अनुमानित भंडार 1 मिलियन टन है और व्यापक ज्ञाना कजाकिस्तान क्षेत्र में संभावित भंडार 20 मिलियन टन से अधिक है। अस्ताना से लगभग 300 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित यह खोज कजाकिस्तान को वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में एक संभावित प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है, खासकर तब जब दुनिया हरित प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रही है और चीन जैसे आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य बना रही है।
- तेल-समृद्ध मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन 12 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार है, जिसमें तख्तापलट के प्रमुख ब्राइस ओलिगुई नगुएमा को प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव अगस्त 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद देश के सैन्य शासन से नागरिक शासन की ओर परिवर्तन की दिशा में एक निर्णायक क्षण है, जिसने बॉन्गो परिवार के पाँच दशकों से अधिक समय के शासन का अंत किया था। नगुएमा, जिन्होंने इस तख्तापलट का नेतृत्व किया, खुद को "जनता का उम्मीदवार" बताते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
- ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर 104% टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और तेज़ हो गया, जिसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 34% से बढ़कर 84% टैरिफ लगा दिया। तीखी प्रतिक्रिया में, चीन ने 12 अमेरिकी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया, छह को अपनी अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में शामिल कर लिया, दुर्लभ मृदाओं पर निर्यात नियंत्रण लागू कर दिया और अमेरिका पर वैश्विक व्यापार स्थिरता को बाधित करने का आरोप लगाते हुए WTO में शिकायत दर्ज कराई।





बैंकिंग और फाइनेंस

क्रमांक	बैंक का नाम	उद्देश्य / योजना का विवरण
1	एक्सिस बैंक	एक्सिस बैंक ने जे.पी. मॉर्गन और उसकी ब्लॉकचेन इकाई Kinexys के साथ मिलकर भारत की पहली 24/7 अमेरिकी डॉलर भुगतान सेवा शुरू की है, जो GIFT सिटी से संचालित होती है। यह सेवा तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाती है, लागत घटाती है और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करती है। यह रविवार को कार्य दिवस मानने वाले मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार में सहायक है।
2	बंधन बैंक	अप्रैल 2025 में, बंधन बैंक ने उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों (HNIs) के लिए "एलीट प्लस सेविंग्स अकाउंट" लॉन्च किया। इसमें असीमित नकद जमा और बेहतर बीमा कवरेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	बॉब स्कॉयलर ड्राइव डिपॉजिट योजना शुरू की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.80% तक का ब्याज दर प्रदान किया जा रहा है। यह योजना आम ग्राहकों के लिए भी आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करती है।

आरबीआई समाचार

विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित समसामयिक मामले

क्रमांक	नाम	उद्देश्य / विवरण
1	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• RBI की 90वीं वर्षगांठ वर्ष 2025 में मनाई गई। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। यह आर्थिक सुधारों (1991), डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में अग्रणी रहा है। पहले गवर्नर सर ऑस्वॉर्ड स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सर सी.डी. देशमुख थे।
2	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 2 अप्रैल 2025 को RBI ने घोषणा की कि ₹2000 के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में लौट चुके हैं। केवल ₹6,366 करोड़ नोट ही अभी जनता के पास हैं। यह प्रक्रिया मई 2023 में ₹2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा के बाद शुरू हुई थी।
3	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 1 अप्रैल 2025 से 500 कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को Supervisory Action Framework (SAF) से Prompt Corrective Action (PCA) Framework में लाया जाएगा ताकि वित्तीय स्थिरता और नियामकीय निगरानी को मजबूत किया जा सके।
4	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• सरकार द्वारा गारंटीकृत सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) पर RBI ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो ARC (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों) के माध्यम से बुरे ऋणों के समाधान को बेहतर बनाएंगे। इसमें पूंजी उपचार में सख्ती, NAV आधारित मूल्यांकन और प्रोविजन की वापसी जैसे प्रावधान शामिल हैं।
5	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• ATM निकासी शुल्क 1 मई 2025 से ₹21 से बढ़ाकर ₹23 कर दिया गया है, जो मुफ्त सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। अपने बैंक के एटीएम से 5, मेट्रो में अन्य बैंकों से 3 और गैर-मेट्रो में 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन की अनुमति पहले जैसी बनी रहेगी।
6	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• RBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए निवेश सीमाएं FY 2025-26 में यथावत रखी हैं: केंद्र सरकार के बॉन्ड (G-Secs) के लिए 6%, राज्य विकास ऋणों (SDLs) के लिए 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए 15%। अप्रैल-सितंबर 2025 के लिए G-Secs सीमा ₹2.79 ट्रिलियन और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ₹8.22 ट्रिलियन निर्धारित की गई है।
7	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• RBI ने NPCI को UPI P2M (पर्सन-टू-मर्चेन्ट) ट्रांजेक्शन सीमा बढ़ाने की अनुमति दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान जैसे क्षेत्रों में यह सीमा ₹2-5 लाख तक की जा सकती है। P2P सीमा ₹1 लाख पर यथावत है। यह निर्णय डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है।
8	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• RBI ने 'RBI कहता है' अभियान के अंतर्गत अपना सरकारी और सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव को बढ़ावा देना है। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाने में सहायक होगी।





अर्थव्यवस्था और व्यापार

अप्रैल 2024 के अनुसार जीडीपी और विकास दर

- आर्थिक गतिविधियों और अनुपालन में वृद्धि के कारण भारत का जीएसटी संग्रह मार्च 2025 में सालाना आधार पर 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें सीजीएसटी (38,100 करोड़ रुपये), एसजीएसटी (49,900 करोड़ रुपये), आईजीएसटी (95,900 करोड़ रुपये) और जीएसटी उपकर (12,300 करोड़ रुपये) शामिल हैं। रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.76 लाख करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 7.3% वृद्धि) रहा। वित्त वर्ष 2025 में कुल जीएसटी राजस्व 22.08 लाख करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 9.4% वृद्धि) रहा, जो सरकार के 11% जीएसटी राजस्व अनुमान के अनुरूप है।
- ईवाई इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट में वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें संतुलित राजकोषीय रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देती है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सरकारी निवेश, उच्च राजस्व-से-जीडीपी अनुपात और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए समान हस्तांतरण के महत्व पर प्रकाश डालता है।

व्यापार समाचार

- रेनॉल्ट समूह निसान मोटर कॉर्प से रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (RNAIPL) में शेष 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, जिससे चेन्नई विनिर्माण सुविधा का 100% स्वामित्व प्राप्त होगा। यह 2023 के एक समझौते के बाद हुआ है जिसमें रेनॉल्ट और निसान ने भारतीय बाजार के लिए छह नए मॉडल विकसित करने के लिए \$600 मिलियन का निवेश किया था। 2010 में एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित RNAIPL में निसान ने 2023 में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% कर ली। यह अधिग्रहण रेनॉल्ट के भारतीय विनिर्माण पर नियंत्रण को मजबूत करता है और इसकी व्यापक वैश्विक पुनर्गठन रणनीति का समर्थन करता है।
- मार्च 2025 में UPI लेन-देन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो 24.77 ट्रिलियन रुपये मूल्य और 19.78 बिलियन वॉल्यूम तक पहुंच गया, जो फरवरी से मूल्य में 13% और वॉल्यूम में 14% की वृद्धि दर्शाता है। यह मील का पत्थर भारत में मजबूत डिजिटल भुगतान अपनाने को दर्शाता है। वित्त वर्ष 25 के लिए, UPI ने 260.56 ट्रिलियन रुपये के लेन-देन मूल्य (+30% YoY) और 131.14 बिलियन लेन-देन (+42% YoY) देखे, जिसने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसके प्रभुत्व को मजबूत किया।

- आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) ने SEBI, RBI, NCLT, शेयरधारकों और लेनदारों से मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल, 2025 से अपनी NBFC सहायक कंपनी आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (ABFL) का सफलतापूर्वक विलय कर दिया है। विलय का उद्देश्य कॉर्पोरेट संरचना को सरल बनाना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और दक्षता में सुधार करना है। विशाखा मुल्ये को MD और CEO नियुक्त किया गया है, जबकि राकेश सिंह कार्यकारी निदेशक और CEO (NBFC) के रूप में काम करेंगे।
- एचआईएल लिमिटेड ने खुद को बिरलानू लिमिटेड के रूप में पुनः ब्रांड किया है, जो निर्माण सामग्री उद्योग में नवाचार, गुणवत्ता और स्थिरता के अपने मूल मूल्यों के साथ अपनी पहचान को जोड़ता है। भारत और यूरोप में मजबूत उपस्थिति के साथ, कंपनी का लक्ष्य घर के मालिकों, बिल्डरों और डिजाइनरों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। आठ दशकों से अधिक समय से परिचालन में रहने के बाद, बिरलानू हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गहराई से जड़ें जमा चुका है।
- बेंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता जसपे, सॉफ्टबैंक और एक्सेल की भागीदारी के साथ केदारा कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज डी फंडिंग राउंड में \$60 मिलियन जुटाने के बाद 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। इस फंडिंग ने जसपे के मूल्यांकन को \$1 बिलियन के पार पहुंचा दिया। कंपनी की योजना AI के माध्यम से अपनी तकनीक को बढ़ाने और APAC, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यूके और उत्तरी अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने की है। रेजरपे और फोनपे जैसे प्रमुख ग्राहकों के खोने जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, जसपे का लक्ष्य विकास की गति को बनाए रखने के लिए AI-आधारित उत्पादकता और वैश्विक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है।

BANK MAHAPACK

for all Bank & Insurance
Exams

Selection Ka Saathi





समझौता ज्ञापन एवं समझौते

देश के साथ समझौता ज्ञापन

देश	समझौता ज्ञापन	उद्देश्य
भारत	रूस	<ul style="list-style-type: none"> नई दिल्ली में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत-रूस कार्य समूह (आईआरडब्ल्यूजी-पीआईपी) के 8वें सत्र में, भारत और रूस द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए छह नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमत हुए। अमरदीप सिंह भाटिया (भारत) और व्लादिमीर इलिचेव (रूस) की सह-अध्यक्षता में, सत्र में व्यापार, तकनीकी सहयोग और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। 80 से अधिक प्रतिभागियों वाले दूसरे भारत-रूस निवेश फोरम ने संयुक्त उद्यमों में बढ़ती रुचि को प्रदर्शित किया।

संगठन के बीच समझौता ज्ञापन

संस्था	समझौता (MoU) किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
इंडिया पोस्ट	निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड	इंडिया पोस्ट ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए डोर-टू-डोर केवाईसी सत्यापन सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
		इस पहल का उद्देश्य निवेश को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, बुजुर्ग नागरिकों और गतिशीलता में कठिनाई झेलने वाले लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
		इंडिया पोस्ट का व्यापक राष्ट्रीय नेटवर्क पहले ही UTI और SUUTI के लिए 5 लाख से अधिक केवाईसी सत्यापन कर चुका है। यह साझेदारी 'जन निवेश' पहल को समर्थन देती है, जो नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक वित्तीय सेवाओं से सशक्त बनाती है।

नियुक्तियाँ और इस्तीफे

नियुक्तियाँ राष्ट्रीय

व्यक्ति का नाम	नियुक्ति के रूप में	संगठन / स्थान	मुख्य विवरण
डॉ. जय भट्टाचार्य	निदेशक	नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH), अमेरिका	राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित, 25 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने पुष्टि की; स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता।
निधि तिवारी	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव	प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), भारत	पूर्व में उप सचिव के रूप में कार्य किया; कूटनीति और वैश्विक सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञ।
अम्बुज चंदना	प्रबंध निदेशक एवं उपभोक्ता बैंकिंग प्रमुख	डीबीएस बैंक इंडिया	कोटक महिंद्रा बैंक में 16 वर्षों का अनुभव; रिटेल बैंकिंग और कर्ज सेवाओं में विशेषज्ञता।
सलीला पांडे	एमडी और सीईओ	एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट सर्विसेस	अप्रैल 2025 से प्रभावी नियुक्ति; एसबीआई में 30 वर्षों का अनुभव, खुदरा बैंकिंग और क्रेडिट सेवाओं में दक्ष।
एन. चंद्रशेखरन	सलाहकार परिषद के सदस्य	IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष)	IMF की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में नियुक्त; वैश्विक व्यापार रणनीति और नीति में प्रभावशाली भूमिका।
स्वामीनाथन एस. अय्यर	पूर्णकालिक सदस्य (जीवन बीमा)	IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त; बीमा क्षेत्र में नीतिगत और विनियामक मामलों की देखरेख करेंगे।
पूनम गुप्ता	डिप्टी गवर्नर	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	माइकल पात्रा का स्थान लिया; NCAER, IMF और वित्त आयोग में अनुभव; मौद्रिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका।
एच. शंकर	प्रबंध निदेशक (MD)	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL)	पहले से कार्यवाहक एमडी; रिफाइनरी आधुनिकीकरण और स्थायी ऊर्जा परियोजनाओं में अग्रणी।
शिवसुब्रमण्यम रामन	अध्यक्ष	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)	5 वर्षों के लिए नियुक्त; APY और NPS के नियमन और विस्तार में भूमिका निभाएंगे।





व्यक्ति का नाम	नियुक्ति के रूप में	संगठन / स्थान	मुख्य विवरण
कमल हासन	अध्यक्ष	FICCI मीडिया और एंटरटेनमेंट समिति दक्षिण	भारतीय M&E उद्योग को \$100 अरब का बनाने का विजन; रचनात्मकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर बल।
सोहिनी राजोला	कार्यकारी निदेशक	नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)	NPCI की भुगतान सेवाओं को बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारियों के विकास की जिम्मेदारी।
मोहसिन नकवी	अध्यक्ष	एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC)	पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री; ACC में एशियाई क्रिकेट को वैश्विक मंच पर सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता।
सीमा अग्रवाल	डीजीपी / अग्निशमन और बचाव सेवा निदेशक	भारत (राज्य स्तरीय)	वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी; खाद्य आपूर्ति विभाग में पूर्व डीजीपी।
बालाजी नुथलापाडी	कार्यकारी निदेशक - प्रौद्योगिकी और संचालन	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक	20 वर्षों का अनुभव; सिटी बैंक के एमडी रहे; डिजिटल बैंकिंग और संचालन में दक्षता।
जस्टिस अरुण पाली	मुख्य न्यायाधीश	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट	पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश; संविधान, श्रम, औद्योगिक और दीवानी मामलों में विशेषज्ञता।
सतीश चव्वा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	ओमान-इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड (OIJIF)	प्राइवेट इक्विटी और वित्त में 20 वर्षों का अनुभव; निवेश प्रदर्शन और सतत विकास पर केंद्रित।
वीरल दवडा	उप मुख्य सूचना अधिकारी (Deputy CIO)	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)	NCDEX में पूर्व CTO; हाइब्रिड क्लाउड, डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं में नेतृत्व।
डॉ. मोहन राजन	उपाध्यक्ष	ऑल इंडिया ऑपथोलॉजिकल सोसाइटी (AIOS)	राजन आई केयर हॉस्पिटल के चेयरमैन; तमिलनाडु से AIOS में यह पद प्राप्त करने वाले पाँचवें विशेषज्ञ।
डॉ. नीलम हुंगाना तिम्लीना	कार्यवाहक गवर्नर	नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB)	वरिष्ठ उप गवर्नर रहीं; महा प्रसाद अधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नियुक्त।

पुरस्कार

अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार

पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता	क्षेत्र	मुख्य जानकारी
प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार	पुरातत्ववेत्ता मायना स्वामी	ऐतिहासिक अनुसंधान एवं सामाजिक सेवा	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक शोध और समाज सेवा में योगदान हेतु सम्मान; कलारत्न उपाधि, हंस पदक, प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार के साथ दिया गया।
गोल्ड मर्करी पुरस्कार - शांति और स्थिरता हेतु	दलाई लामा	विश्व शांति एवं पर्यावरण	गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल द्वारा धर्मशाला में सम्मानित; अहिंसा, मानवीय गरिमा, धर्मों के बीच संवाद और पर्यावरण संरक्षण में आजीवन योगदान के लिए।
उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार	निखिल सिंघल	जनसंपर्क एवं रणनीतिक संचार	तपस्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में ताज लखनऊ में सम्मानित; पीआर और जनसंचार में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सम्मानित।
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार	आकाश श्रोफ	सामाजिक सेवा एवं शिक्षा	युवास्पार्क के संस्थापक; आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा नवाचार में योगदान हेतु केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा संसद भवन में सम्मानित।
फ्रेड डेरिंगटन कला और संस्कृति उत्कृष्टता पुरस्कार	सुदर्शन पटनायक	रेत कला	भगवान गणेश की 10 फीट ऊँची रेत मूर्ति "विश्व शांति" संदेश के साथ; सैंडवर्ल्ड, इंग्लैंड में प्रदर्शित; इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय शिल्पकार।
राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार	राजेश उन्नी	समुद्री क्षेत्र	सायनेजी मरीन ग्रुप के संस्थापक; भारत के सर्वोच्च समुद्री सम्मान से 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर मुंबई में सम्मानित।





शिखर सम्मेलन, कार्यक्रम और सम्मेलन

Category	Event	Key Points
शिखर सम्मेलन	9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (जीटीएस) 2025	<ul style="list-style-type: none"> विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (जीटीएस) 2025, 10-12 अप्रैल को नई दिल्ली में "संभावना" थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां समावेशी विकास, डिजिटल शासन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे सकती हैं, जिसमें 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे।
घटनाक्रम	11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक	<ul style="list-style-type: none"> ब्रासीलिया में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक (3 अप्रैल, 2025) में, भारत ने मजबूत जलवायु सहयोग का आह्वान किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए बाकू से बेलेम रोडमैप पर जोर दिया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अमनदीप गर्ग द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत ने सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा और न्यायोचित परिवर्तन पर प्रकाश डाला। भारत ने ब्रिक्स की वैश्विक भूमिका पर जोर दिया, जिसमें दुनिया की 47% आबादी और सकल घरेलू उत्पाद का 36% शामिल है, और उन्नत जलवायु वित्त, ऊर्जा विविधीकरण और ग्रीन ग्रिड पहल की वकालत की। बैठक में संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया।
घटनाक्रम	लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों का संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी कार्य समूह (आईएसएआर)	<ul style="list-style-type: none"> भारत को 2025-2027 के कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों (आईएसएआर) पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी कार्य समूह में नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नियुक्ति भारत के बढ़ते प्रभाव और अपनी क्षमताओं में विश्वास को रेखांकित करती है, विशेष रूप से पारदर्शिता, जवाबदेही और कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने में। आईएसएआर के सदस्य के रूप में, भारत यूएनसीटीएडी की छत्रछाया में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय मुद्दों और शासन जैसे क्षेत्रों सहित वित्तीय और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देगा।
घटनाक्रम	वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद	<ul style="list-style-type: none"> ब्राजील ने बेलेम, ब्राजील (नवंबर 2025) में होने वाले COP30 से पहले वैश्विक समन्वय को बढ़ाने और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए UNFCCC के तहत एक वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। जटिल जलवायु वार्ता को सरल बनाने के उद्देश्य से, प्रस्ताव प्रभावी निर्णय लेने को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हालाँकि इसे मिश्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ मिली हैं, लेकिन यह जलवायु संकट से निपटने में ब्राजील की सक्रिय भूमिका को उजागर करता है।
सम्मेलन	'पर्यावरण - 2025' पर राष्ट्रीय सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में (29 मार्च, 2025) 'पर्यावरण-2025' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जिम्मेदारी के रूप में महत्व दिया गया और भावी पीढ़ियों के लिए स्थिरता की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति सहयोग पर चर्चा की गई।
सम्मेलन	सेना कमांडरों का सम्मेलन (एसीसी) 2025	<ul style="list-style-type: none"> सेना कमांडरों का सम्मेलन (एसीसी) 2025 1-4 अप्रैल, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, परिचालन प्राथमिकताओं और उभरती चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ सेना नेतृत्व के लिए एक द्विवार्षिक मंच के रूप में कार्य करेगा। मुख्य चर्चाओं में सैन्य तैयारी, तकनीकी एकीकरण और सैनिक कल्याण शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और नीति आयोग के सीईओ के साथ, भारत के रक्षा दृष्टिकोण और राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों की भूमिका पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।
सम्मेलन	बड़ी एनबीएफसी के लिए सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 28 मार्च, 2025 को चेन्नई में बड़ी NBFC कंपनियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका विषय था "साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: NBFC को मजबूत बनाना।" RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे और ICAI के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विनियामक पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन, निष्पक्ष ऋण देने की प्रथाओं और लेखा परीक्षा पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया।





Category	Event	Key Points
सम्मेलन	6वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल, 2025 को 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंचे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बिम्सटेक देशों के बीच व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। शिखर सम्मेलन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-थाईलैंड सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला और क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के बाद, वह राजनयिक जुड़ाव जारी रखने के लिए श्रीलंका का दौरा करेंगे।

इंडेक्स

रैंकिंग

- भारत 2023 में 11,943 करोड़ रुपये (1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निजी एआई निवेश के साथ वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है, जो वैश्विक एआई परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसने UNCTAD 'रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज' इंडेक्स में अपनी स्थिति में सुधार किया, जो 2022 में 48वें स्थान से बढ़कर 2024 में 36वें स्थान पर पहुंच गया। भारत को पवन ऊर्जा में जर्मनी, इलेक्ट्रिक वाहनों में जापान और 5G में दक्षिण कोरिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। 13 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ, भारत एआई अनुसंधान और नैनो प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, लेकिन अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, अनुसंधान एवं विकास और कार्यबल कौशल विकास में निरंतर निवेश आवश्यक है। 2033 तक एआई का आर्थिक प्रभाव 4,09,48,800 करोड़ रुपये (4.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) होने का अनुमान है।
- 7 अप्रैल, 2025 को, MeitY ने CERT-In के माध्यम से, CSIRT-Fin और SISA के साथ मिलकर BFSI क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें साइबर खतरों का गहन विश्लेषण और साइबर सुरक्षा लचीलेपन के लिए एक रोडमैप पेश किया गया। DFS, MeitY और SISA के शीर्ष अधिकारियों द्वारा लॉन्च की गई, रिपोर्ट में AI-संचालित हमलों, विस्तारित डिजिटल हमले सतहों और अनुपालन चुनौतियों से होने वाले जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है। यह एक एकीकृत साइबर सुरक्षा रणनीति पर जोर देता है और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी में उपायों की सिफारिश करता है, जिसका उद्देश्य खतरों का अनुमान लगाना, सुरक्षा को मजबूत करना और सहयोगी खुफिया-साझाकरण के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
- Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स (फरवरी 2025) के अनुसार, मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे कम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की, जो 58.24 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड के साथ वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर रहा, जबकि दिल्ली 91.11 एमबीपीएस के साथ 89वें स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर रहा। इस असमानता ने वैश्विक ब्रॉडबैंड रैंकिंग में भारत की समग्र गिरावट में योगदान दिया, जो 94 से 95 तक पहुंच गई, जिसमें राष्ट्रीय औसत 61.66 एमबीपीएस डाउनलोड, 57.89 एमबीपीएस अपलोड और 7 एमएस विलंबता है। मुंबई के खराब प्रदर्शन का कारण घनी आबादी और चुनौतीपूर्ण इलाका है।

रिपोर्ट

रिपोर्ट का नाम	जारीकर्ता	मुख्य बिंदु
यूनेस्को रिपोर्ट	यूनेस्को रिपोर्ट	<p>"Nutrition for Growth" कार्यक्रम (27-28 मार्च, 2025, फ्रांस में) में स्कूल भोजन की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> 2024 में 47% प्राथमिक विद्यार्थियों को भोजन मिला, परंतु कई में पोषण की कमी रही। 27% स्कूल भोजन योजनाओं में पोषण विशेषज्ञों की भागीदारी नहीं। 187 में से सिर्फ 93 देशों के पास स्कूल भोजन हेतु विधिक प्रावधान। 65% देशों ने खाद्य मानक निर्धारित किए हैं।
2025 तकनीक और नवाचार रिपोर्ट	UNCTAD	<p>भारत ने अग्रणी तकनीकों को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।</p> <ul style="list-style-type: none"> वैश्विक रैंकिंग में 2022 में 48वें स्थान से बढ़कर 2025 में 36वां स्थान। आईसीटी, अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक क्षमता और वित्त क्षेत्र में प्रगति। विशेष रूप से AI और नैनो तकनीक में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। भारत उन विकासशील देशों में शामिल है जो अपेक्षाओं से बेहतर तकनीकी तैयारी दिखा रहे हैं।





रक्षा

अभ्यास

अभ्यास का नाम	स्थान / भागीदार देश	मुख्य बिंदु
INIOCHOS-25	यूनान (ग्रीस)	<p>भारतीय वायुसेना (IAF) ने 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक एंड्राविडा एयर बेस, ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS-25 में भाग लिया।</p> <ul style="list-style-type: none"> शामिल विमान: Su-30 MKI, IL-78, C-17। उद्देश्य: युद्ध संचालन क्षमता, संयुक्त रणनीति, और सामरिक विशेषज्ञता को बढ़ाना। भागीदार देश: 15। द्विवार्षिक अभ्यास में यथार्थवादी युद्ध परिदृश्य शामिल हैं।
टाइगर ट्रायंग 2025	भारत (विशाखापट्टनम और काकीनाडा)	<p>INUS भारत-अमेरिका त्रि-सेवा द्विपक्षीय HADR अभ्यास का चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित।</p> <ul style="list-style-type: none"> उद्देश्य: आपदा राहत और मानवीय सहायता में एकरूपता। SOPs और संयुक्त समन्वय केंद्र (CCC) पर कार्य। हार्बर फेज: विशाखापट्टनम (1-7 अप्रैल), सी फेज: काकीनाडा तट (8-13 अप्रैल)। सम्मिलित अभ्यास: समुद्री, उभयचर और चिकित्सा सहायता अभियान।
इंद्रा 2025 अभ्यास	भारत और रूस	<p>INRU भारतीय और रूसी नौसेना के बीच 14वाँ संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक आयोजित।</p> <ul style="list-style-type: none"> उद्देश्य: समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला, समन्वित संचालन और युद्धाभ्यास। शामिल गतिविधियाँ: जटिल युद्धाभ्यास, संयुक्त संचालन क्षमता और सर्वोत्तम अभ्यासों का आदान-प्रदान।

सौदा और समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये (2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.04% की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी उद्योग द्वारा संचालित यह उछाल रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। डीपीएसयू ने 42.85% की वृद्धि दर्ज की, जिसका योगदान 8,389 करोड़ रुपये रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 15,233 करोड़ रुपये रहा।

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

नाविका सागर परिक्रमा II (NSP-II), भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा एक वैश्विक परिक्रमा अभियान, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचा, जो इसकी 23,400 समुद्री मील की यात्रा का चौथा चरण था। 2 अक्टूबर, 2024 को गोवा से रवाना हुए इस अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, समुद्री अनुसंधान और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। पोत INSV तारिणी पहले फ्रेमेंटल (ऑस्ट्रेलिया), लिटलटन (न्यूजीलैंड) और पोर्ट स्टेनली (फॉकलैंड्स, यूके) में रुका था और मई 2025 में वापस आएगा। भारतीय सेना ने कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए अप्रैल 2025 में जुबर स्टेडियम, बटालिक में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं को जोड़ना और क्षेत्रीय विकास का समर्थन करना था। इसमें 13 टीमों ने भाग लिया, जिसमें बटालिक ए ने 47 रनों से जीत दर्ज की। एक अनूठी पहल में एक युवा उद्यमी से स्थानीय रूप से निर्मित लद्दाखी विलो क्रिकेट बैट खरीदना शामिल था, जिससे स्थानीय कारीगरों को सहायता मिली। डीआरडीओ और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएम) ने महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है, जिससे भारतीय सेना के लिए इसकी परिचालन तत्परता साबित हुई है। हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई, मिसाइल प्रणाली ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर चार सफल उड़ान परीक्षण किए, जिसमें लंबी दूरी, छोटी दूरी, उच्च ऊंचाई और कम ऊंचाई वाले खतरों को लक्षित किया गया।

Test

Prime

ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION.





भारत ने सरकार-से-सरकार (G2G) समझौते के तहत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए ₹63,000 करोड़ (\$7+ बिलियन) के सौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे नौसेना विमानन और INS विक्रांत पर वाहक-आधारित वायु शक्ति में वृद्धि होगी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) द्वारा स्वीकृत इस सौदे में 22 सिंगल-सीटर, 4 ट्विन-सीटर ट्रेनर जेट के साथ-साथ बेड़े के रखरखाव, हथियार प्रणाली, प्रशिक्षण और स्वदेशी विनिर्माण और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ऑफसेट दायित्व शामिल हैं।

विज्ञान प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय

- आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने साइबर कमांडो के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, जो भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए साइबर कमांडो कार्यक्रम ने बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों में 37 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।
- Techvantage.ai द्वारा CrewAI के सहयोग से आयोजित भारत का पहला एजेंटिक AI हैकथॉन, एजेंटिक AI सप्ताह के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें देशभर में 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कई शहरों में आयोजित और केरल के टेक्नोपार्क में समापन हुआ, महीने भर चलने वाला यह कार्यक्रम BFSI क्षेत्र के लिए स्वायत्त AI समाधानों पर केंद्रित था, जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाने, क्रेडिट स्कोरिंग और विनियामक अनुपालन जैसी चुनौतियों से निपटना शामिल था, जो भारत के AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ी छलांग है।

अंतरराष्ट्रीय

- Microsoft 4 अप्रैल, 2025 को अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो PC सॉफ्टवेयर अग्रणी से क्लाउड कंप्यूटिंग और AI में वैश्विक तकनीकी नेता के रूप में इसके विकास को चिह्नित करता है। बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा 1975 में स्थापित, Microsoft ने MS-DOS के साथ कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी, बाद में Windows और उत्पादकता उपकरणों के साथ हावी हो गया। अब, यह भविष्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए AI नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो रही है।

- 6 अप्रैल, 2025 को, CEO मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा ने अपने अगली पीढ़ी के लामा-4 AI सूट को लॉन्च किया, जिसमें तीन अत्याधुनिक मॉडल शामिल हैं - स्काउट (एक शीर्ष-स्तरीय मल्टीमॉडल मॉडल), मावरिक (मेटा का प्रमुख AI सहायक), और बेहेमोथ (इसका सबसे शक्तिशाली LLM, जिसे शिक्षक मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया गया है)। यह रणनीतिक कदम वैश्विक AI दौड़ में मेटा की स्थिति को मजबूत करता है, जो सीधे OpenAI के ChatGPT, Google के Gemini और चीन के DeepSeek जैसे उभरते खिलाड़ियों को चुनौती देता है।
- बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है, जो शांतिपूर्ण, टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश के रक्षा सचिव अशरफ उद्दीन के नेतृत्व में हस्ताक्षर, सुरक्षित अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। आर्टेमिस समझौते, बाहरी अंतरिक्ष संधि जैसे ढाँचों पर आधारित हैं, जो सहयोगात्मक अंतरिक्ष गतिविधियों में राष्ट्रों का मार्गदर्शन करते हैं, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना और मंगल ग्रह का अन्वेषण करना है। बांग्लादेश की भागीदारी अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी भूमिका को बढ़ाती है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों और नासा के साथ संबंधों को बढ़ावा देती है।
- डलास स्थित बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने 12,500 साल बाद विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ (कैनिनस डायरस) को CRISPR जीन-एडिटिंग और प्राचीन जीवाश्मों से डीएनए का उपयोग करके पुनर्जीवित करके इतिहास रच दिया है। ग्रे वुल्फ कोशिकाओं और घरेलू कुत्तों के सरोगेट्स का उपयोग करके तीन डायर वुल्फ पिल्लों- रोमुलस, रेमस और खलीसी का जन्म हुआ। हालाँकि इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन इस सफलता को प्रामाणिकता और आधुनिक अनुकूलनशीलता पर पारिस्थितिक और नैतिक चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।

खेल

क्रिकेट

- विराट कोहली ने मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में आरसीबी और एमआई के बीच आईपीएल 2025 के मुकाबले के दौरान टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया। 36 साल की उम्र में, आरसीबी के आइकन इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पांचवें और दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए, जिससे खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उनकी महानता और मजबूत हो गई।

बैडमिंटन और टेनिस

- बॉम्बे जिमखाना, मुंबई (24-28 मार्च, 2025) में आयोजित इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट में अनाहत सिंह ने अपना 11वां पीएसए खिताब जीता, जिससे भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति फिर से पुख्ता हुई, जबकि करीम एल टॉर्की (मिस्र, विश्व नंबर 64) ने पुरुष एकल फाइनल में अभय सिंह (भारत) के खिलाफ जीत हासिल की। 53,500 डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ, यह 2018 के बाद से भारत का सबसे अधिक रेटिंग वाला पीएसए इवेंट था और देश में आयोजित पहला पीएसए कॉपर इवेंट था।





- विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सवालेंका ने फाइनल में जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर मियामी ओपन का अपना पहला खिताब जीता, इस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में कोई भी सेट गंवाए बिना खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही उन्होंने 19वां WTA खिताब अपने नाम कर लिया, जिसमें 8 WTA 1000 खिताब और 3 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं। सवालेंका का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने पहले सेट में पेगुला की सर्विस को लव के लिए तोड़ा और दूसरे सेट में आक्रामक शॉट-मेकिंग का प्रदर्शन किया।

हॉकी

- भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 साल के शानदार करियर के बाद 2 अप्रैल, 2024 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। 32 वर्षीय स्ट्राइकर, जिन्होंने 320 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 158 गोल किए हैं, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। कटारिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी भावनात्मक विदाई साझा की, जिसमें उन्होंने अपने करियर के "चरम" पर कदम पीछे खींचने के अपने फैसले पर ज़ोर दिया, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खेल को छोड़ने का फैसला किया।

एथलेटिक और फुटबॉल

- भारत ने ब्राजील के फोज डू इगुआकु में 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में ऐतिहासिक शुरुआत की, हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। उनकी जीत तब हुई जब उनके प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के ओडेल कामारा चोट के कारण प्रतियोगिता से हट गए। अभिनाश जामवाल ने 65 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि जदुमणि सिंह मंडेंगबाम, मनीष राठौर, सचिन और विशाल ने कांस्य पदक जीते। भारत ने कुल छह पदक जीते, जो विश्व मुक्केबाजी कप में अपनी पहली भागीदारी में एक मजबूत प्रदर्शन था, जिसने 2028 ओलंपिक से पहले एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया।
- भारत ने अम्मान में 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन कुश्ती में दमदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। मनीषा भानवाला (62 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक पुनिया (92 किग्रा), उदित (61 किग्रा) और रीतिका हुड्डा (76 किग्रा) ने रजत पदक जीता। अंतिम पंगल (53 किग्रा) और दिनेश (125 किग्रा) सहित छह पहलवानों ने कांस्य पदक जीता। 30 सदस्यीय दल में मानसी लाठेर और मुकुल दहिया जैसी शीर्ष प्रतिभाएँ शामिल थीं, जिन्होंने महाद्वीपीय कुश्ती में भारत के प्रभुत्व को मजबूत किया।

अन्य खेल समाचार

- आदित्य बिडला मेमोरियल पोलो कप 2025 का समापन नई दिल्ली में एक रोमांचक फाइनल में रजनीगंधा अचीवर्स द्वारा जिंदल पैथर को हराने के साथ हुआ। विजेता टीम में डिनो धनखड़, शमशीर अली, अभिमन्यु पाठक और डैनियल ओटामेंडी शामिल थे, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, राजश्री बिडला और असकरण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित ट्रॉफी हासिल की। आदित्य विक्रम बिडला के पोलो के प्रति जुनून का सम्मान करने वाले इस टूर्नामेंट में कैवेलरी रॉयल एनफील्ड ने भी भाग लिया, जिसमें शीर्ष अंतरराष्ट्रीय पोलो प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया।
- फ्रांसेस्को बैगनिया ने अमेरिका के ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की, जब मार्क मार्केज़ सर्किट ऑफ़ द अमेरिकाज़ (COTA) में नौवें लैप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। डुकाटी ने पोडियम पर अपना दबदबा बनाया, एलेक्स मार्केज़ दूसरे और फैबियो डि जियानान्टोनियो तीसरे स्थान पर रहे, जिससे डुकाटी की लगातार 20वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत दर्ज हुई, जो होंडा के रिकॉर्ड (22) से सिर्फ़ दो जीत पीछे है।
- युवा भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने 25-30 मार्च, 2025 को बेल्जियम में आयोजित एज़ेलहोफ़ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। CSI2-1- YH - LIER - स्प्रिंग टूर** श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करते हुए, निहारिका ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। हॉटिस चारबोनियर की सवारी करते हुए, उन्होंने अंतिम दो-चरण विशेष स्पर्धा में 34.48 और 31.95 के पेनल्टी पॉइंट के साथ स्वर्ण पदक जीता।
- मैक्स वस्टेंपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में 2025 फॉर्मूला 1 सीज़न की अपनी पहली रेस जीती, जिससे उनकी लगातार चौथी जीत सुनिश्चित हुई। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियान्नी के साथ एक करीबी मुकाबले के बाद, वस्टेंपेन ने रणनीतिक पिट स्टॉप और टायर विकल्पों की मदद से बढ़त बनाए रखी। पोल पोजिशन के लिए क्वालीफाइंग में उन्होंने नॉरिस को सिर्फ़ 0.012 सेकंड से पीछे छोड़ा। यह रेस रेड बुल के लिए भी महत्वपूर्ण थी, जो होंडा पावर के साथ उनकी आखिरी रेस थी। वस्टेंपेन ने स्टैंडिंग में अपनी बढ़त को बढ़ाया, अब नॉरिस से सिर्फ़ एक अंक आगे हैं। अन्य उल्लेखनीय फिनिश में चार्ल्स लेक्लर (फेरारी) चौथे और जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज) पांचवें स्थान पर रहे।



BANK MAHAPACK

for all Bank & Insurance Exams

Selection Ka Saathi





पुस्तक एवं लेखक

पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
द ग्रेट कंसिलिएटर: लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया	संजीव चोपड़ा	संजीव चोपड़ा की यह पुस्तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और विरासत पर आधारित है। लेखक ने शास्त्री जी के उन योगदानों को उजागर किया है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की स्थापना और उनका प्रसिद्ध नारा "जय जवान, जय किसान"।
द इंडिया आई सॉ	एस. अम्बुजम्मल	एस. अम्बुजम्मल (1899-1981) की आत्मकथा "नान कांडा भारतम्" का अनुवाद "द इंडिया आई सॉ" के रूप में हुआ। एक प्रतिष्ठित अयंगर परिवार में जन्मी, उन्होंने उपेक्षा, अवांछित जन्म और कठिन विवाह जैसी व्यक्तिगत चुनौतियों को पार किया और एक प्रमुख गांधीवादी व समाज सुधारक बनीं। यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और महिला कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
केयरलेस पीपल	सारा वायन-विलियम्स	फेसबुक (अब मेटा) की पूर्व ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर सारा वायन-विलियम्स की यह संस्मरणात्मक पुस्तक, फेसबुक के भीतर की विघातक कार्यसंस्कृति को उजागर करती है। इसमें मार्क जुकरबर्ग, शेरेल सैंडबर्ग और जोएल कैपलान जैसे शीर्ष नेतृत्व की अनैतिकता और निजी दुर्व्यवहार की बात की गई है। पुस्तक में 2016 के अमेरिकी चुनाव, म्यांमार संकट में फेसबुक की भूमिका और चीन में प्रवेश के प्रयासों का भी उल्लेख है।

निधन

राष्ट्रीय

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य बिंदु
1	मनोज कुमार	बॉलीवुड अभिनेता	पाकिस्तान (विभाजन के बाद दिल्ली आए)	प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में हृदय संबंधी समस्याओं और लिवर सिरोसिस के कारण निधन हो गया। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। उन्होंने हरियाली और रास्ता (1962), वो कौन थी? (1964), पत्थर के सनम (1967) जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पाई और देशभक्ति पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं।
2	रविकुमार	मलयालम और तमिल फिल्म अभिनेता	चेन्नई	दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रविकुमार का 4 अप्रैल 2025 को 71 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वे अभिनेता भारती और निर्माता के.एम.के. मेनन के पुत्र थे। उल्लासा यात्रा (1975) और अवरगल (1977) जैसी फिल्मों से लोकप्रिय हुए। उन्होंने रोमांटिक किरदारों से दर्शकों का दिल जीता।
3	पद्मश्री राम सहाय पांडेय	राय लोकनृत्य के प्रख्यात कलाकार	सागर, मध्य प्रदेश	राय लोकनृत्य को सामाजिक कलंक से निकालकर एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक धरोहर में बदलने वाले पद्मश्री राम सहाय पांडेय का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गरीबी, अनाथता और जातीय पूर्वाग्रहों के बावजूद अपने जीवन को राय नृत्य को समर्पित कर दिया।
4	दादी रतन मोहिनी	आध्यात्मिक नेतृत्व	हैदराबाद, सिंध (अब पाकिस्तान में)	ब्रह्माकुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी का 100 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में निधन हो गया। उनका जन्म 25 मार्च 1925 को लक्ष्मी नाम से हुआ था। उन्होंने 2021 में दादी जानकी के बाद यह पद संभाला और विश्व शांति सम्मेलन 1954 सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार किया।





अंतरराष्ट्रीय

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य बिंदु
1	रिचर्ड चेम्बरलेन	हॉलीवुड अभिनेता	बेवर्ली हिल्स, अमेरिका	प्रसिद्ध अभिनेता रिचर्ड चेम्बरलेन, जिन्हें "मिनीसीरीज़ का सम्राट" कहा जाता था, का 90 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2024 को हवाई के वाइमनालो में स्ट्रोक से जुड़ी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उन्होंने कोरियाई युद्ध के बाद पेंटिंग से अभिनय की ओर रुख किया। NBC के डॉ. किलडेर (1961-66) में डॉ. जेम्स किलडेर की भूमिका से प्रसिद्धि पाई। 1963 से 1965 तक "मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार" का खिताब जीता और शो के थीम सॉन्ग की उनकी प्रस्तुति टॉप 40 हिट बनी।
2	वेल किल्मर	हॉलीवुड अभिनेता	लॉस एंजेलिस, अमेरिका	प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता वेल किल्मर का 65 वर्ष की आयु में निमोनिया के कारण निधन हो गया, जिसकी पुष्टि उनकी बेटी मर्सिडीज किल्मर ने की। उन्होंने टॉप गन, द डोर्स, टॉम्बस्टोन और बैटमैन फॉरएवर जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएँ निभाईं। 31 दिसंबर 1959 को जन्मे किल्मर, जूलियाई ड्रामा डिवीजन में सबसे कम उम्र में प्रवेश पाने वाले छात्र थे। उन्होंने मंच से करियर की शुरुआत की और टॉप सीक्रेट! (1984) से हॉलीवुड में कदम रखा, जिससे उन्हें काफी प्रशंसा और फैनबेस मिला।

महत्वपूर्ण दिवस

तारीख	दिवस / पर्व	थीम / विवरण
1 अप्रैल	उत्कल दिवस (उड़ीसा दिवस)	1936 में उड़ीसा को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर भारत का पहला भाषाई राज्य घोषित किया गया था। यह दिन कलिंग की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है।
2 अप्रैल	विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस	2025 की थीम: "न्यूरोडायवर्सिटी और सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को बढ़ावा देना"। यह दिवस ऑटिज़्म से जुड़े लोगों के अधिकार और समावेशी नीतियों को उजागर करता है।
4 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस	2025 की थीम: "सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है"। यह दिन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों के खतरे और उनसे निपटने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
5 अप्रैल	समता दिवस	बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने जातिवाद और लुआछूत के खिलाफ जीवनभर संघर्ष किया। यह दिन समानता और सामाजिक न्याय को समर्पित है।
5 अप्रैल	राष्ट्रीय समुद्री दिवस	1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की पहली समुद्री यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है। भारत की समुद्री शक्ति और व्यापार में योगदान को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है।
6 अप्रैल	स्वामीनारायण जयंती	भगवान श्री स्वामीनारायण (घनश्याम) की जयंती, जो अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे आदर्शों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह राम नवमी के दिन मनाई जाती है।
6 अप्रैल	खेल और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	2025 की थीम: "खेल के ज़रिए सामाजिक समावेशन"। खेल को समानता, शांति और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस	2025 की थीम: "स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य"। यह मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु वैश्विक अभियान की शुरुआत को दर्शाता है।
7 अप्रैल	1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस	1994 में तुत्सी समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। यह नफ़रत, भेदभाव और हिंसा के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
10 अप्रैल	महावीर जयंती	जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2623वीं जयंती। यह दिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों की शिक्षा को दर्शाता है।
10 अप्रैल	विश्व होम्योपैथी दिवस	होम्योपैथी के जनक डॉ. सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथी की "समान से समान इलाज" की अवधारणा और समग्र स्वास्थ्य देखभाल में इसके योगदान को दर्शाता है।





विविध

- बिल्लिंग मटेरियल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण कंपनी HIL लिमिटेड और सीके बिरला ग्रुप का हिस्सा, ने रीब्रांडिंग की है और अब इसे BirlaNu लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह बदलाव निर्माण उद्योग के लिए गुणवत्ता, नवाचार और स्थायी उत्पाद बनाने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- कुंभकोणम पान पत्ता (थंजावुर) और थोवलई फूलों की माला (कन्याकुमारी) को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ, तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। चार महीने की समीक्षा प्रक्रिया के बाद, 30 नवंबर 2024 को सरकारी गजट में इन उत्पादों की आधिकारिक जीआई स्थिति प्रकाशित की गई।
- अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। यह अनूठी हस्तनिर्मित वस्त्र कला गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है।
- मिन्न के रेड सी में 27 मार्च 2025 को हर्गदा तट के पास पर्यटकों के लिए उपयोग की जाने वाली सिनाबाद पनडुब्बी डूब गई। इस दुर्घटना में छह विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जिनमें सभी रूसी नागरिक थे। यह पनडुब्बी 45 विदेशी पर्यटकों और पांच मिस्त्री कू सदस्यों के साथ नियमित यात्रा पर थी जब यह हादसा हुआ।
- पश्चिम बंगाल ने सात नए उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें प्रतिष्ठित नोलेन गुरेर संदेश और बरुईपुर अमरूद शामिल हैं। ये जीआई टैग पारंपरिक वस्तुओं को वैश्विक पहचान प्रदान करेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाएंगे। टैग किए गए उत्पादों में कमरपुकुर के सफेद 'बोंडे', मुर्शिदाबाद के 'छनबोरा' और बिष्णुपुर के 'मोतीचूर लड्डू' जैसे खाद्य पदार्थ, साथ ही राधुनिपागल चावल और मालदा के निस्तारी रेशम यार्न जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं। यह मान्यता पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा करती है और नए बाजार के अवसर खोलती है, हालांकि मिठाइयों की कम शेल्फ लाइफ जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में अब 33 जीआई-टैग वाली वस्तुएं हैं।
- यशराज फिल्मस के बैनर तले बनी शाहरुख खान और काजोल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। डीडीएलजे अब लीसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी, जिससे जुड़ा स्टैच्यू यहां लगेगा। शाहरुख और काजोल का फिल्म के एक सीन का स्टैच्यू 'सीन्स इन द स्क्वायर' में लगेगा। इसकी घोषणा हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस ने की। लीसेस्टर स्क्वायर में 'सीन्स इन द स्क्वायर' मूवी ट्रेल में अब डीडीएलजे के रूप में एक नई प्रतिमा लगेगी। यह हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के 30 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत होगी।

स्थैतिक टेकअवे

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
संगठन		
1	एशियाई विकास बैंक	राष्ट्रपति - मासातो कांडा मुख्यालय - मांडलुयॉन्ग, मनीला, फिलीपींस
2	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा मुख्यालय - मुंबई
3	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेटी मुख्यालय - मुंबई
4	एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाएँ	एमडी और सीईओ - सलिला पांडे
5	डीबीएस बैंक इंडिया	एमडी और सीईओ - रजत वर्मा
6	टाटा संस	अध्यक्ष - नटराजन चन्द्रशेखरन
7	एक्सिस बैंक	एमडी और सीईओ - अमिताभ चौधरी
8	फिक्की	अध्यक्ष - हर्ष वर्धन अग्रवाल
9	आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड	सीईओ - विशाखा मुले
10	रेनॉल्ट ग्रुप	सीईओ - वेंकटराम मामिलापल्ले
11	निसान इंडिया	सीईओ-सौरभ वत्स
12	स्पेस एक्स	सीईओ - एलोन मस्क
13	माइक्रोसॉफ्ट	सीईओ - सत्या नडेला
14	एशियाई क्रिकेट परिषद	अध्यक्ष - मोहसिन नकवी मुख्यालय - दुबई





क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
देश		
15	यूएसए	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प मुद्रा - अमेरिकी डॉलर राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.
16	ब्राजील	राष्ट्रपति - लूला दा सिल्वा मुद्रा - ब्राज़ीलियन रियल राजधानी - ब्राज़ीलिया
17	म्यांमार	राष्ट्रपति - मिन आंग ह्लाईंग (कार्यवाहक) मुद्रा - क्यात राजधानी - नेपीडॉ
18	सिंगापुर	प्रधानमंत्री - लरेंस वोंग मुद्रा - सिंगापुर डॉलर राजधानी - सिंगापुर
19	थाईलैंड	राष्ट्रपति - पैटोंगटार्न शिनावत्रा मुद्रा - थाई बात राजधानी - बैंकॉक
20	जापान	पीएम - इशिबा शिगेरु मुद्रा - यान राजधानी-टोक्यो
21	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन मुद्रा - रूसी रूबल राजधानी - मास्को
राज्य		
22	असम	राज्यपाल- लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सीएम-हेमंत बिस्वा सरमा राजधानी - दिसपुर
23	पंजाब	राज्यपाल- गुलाब चंद सीएम - भगवंत मान राजधानी - चंडीगढ़
24	छत्तीसगढ़	राज्यपाल- रामेन डेका सीएम-विष्णुदेव साय राजधानी - रायपुर
25	पश्चिम बंगाल	राज्यपाल- सी. वी. आनंद बोस मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी राजधानी - कोलकाता
26	महाराष्ट्र	राज्यपाल- सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस राजधानी - मुंबई
27	तेलंगाना	राज्यपाल- जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
28	आंध्र प्रदेश	राज्यपाल- एस. अब्दुल नज़ीर सीएम - चंद्रबाबू नायडू राजधानी - अमरावती
29	ओडिशा	राज्यपाल- हरि बाबू कंभमपति सीएम - मोहन चरण माझी राजधानी-भुवनेश्वर

